including boots, military/safety shoes. Leather garments etc

(c) and (d) There is no specific proposal to utilise the resources of the Public Sector Undertakings to meet the requirements of exporters. However, the exporters are free to negotiate directly with these undertakings for utilising their manufacturing facilities, through mutual agreement.

उरुग्वे दौर की वार्ता के उद्देश्य

2886. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उरुग्वे दौर की वार्ता की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और अभिप्राय क्या है;

(ख) उरुग्वे दौर की वार्ता प्रारम्भ करने में किस देश अथवा किन-किन देशों ने पहल की थी और इसमें उनके क्या हित हैं तथा यह पहल किस तारीख को की गई थी;

(ग) क्या उरुग्वे दौर की वार्ता भारत के साथ चल रही है;

(घ) यदि हां, तो कब से और किन-किन देशों के साथ;

(ङ) उरुग्वे दौर की वार्ता में भारत द्वारा क्या अपेक्षा की जा रही है; और

(च) क्या सरकार ने 1992-93 के वर्ष के अपने बजट प्रस्तावों में उरुग्वे दौर की वार्ता में उठाये जा रहे सभी मुद्दों को स्वीकार कर लिया गया है और किन-किन मुद्दों को अभी स्वीकार किया जाना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्): (क) से (छ) वर्ष 1948 में टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गाट) के शुरू होने के बाद से सदस्य देश टैरिफ और गैर-टैरिफ रियायतों के पारम्परिक आदान-प्रदान के जरिए विश्व व्यापार को उदार बनाने तथा गाट के नियमों एवं नियमावलियों में सुधार करने एवं उनका विस्तार करने के लिए निश्चित समयावधि में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं अथवा व्यापार दौर आयोजित करते रहे हैं। अभी तक ऐसे सात दौर हो चुके हैं। गाट के तत्वावधान में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का आठवां दौर सितम्बर, 1986 में उरुग्वे में शुरू किया गया था और यह उरुग्वे दौर के रूप में जाना जाता है।

उरुग्वे दौर के मूल उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके या इन्हें समाप्त करके विश्व व्यापार को और अधिक उदार बनाना, गाट नियमों एवं निगमावलियों को सुदृढ़ बनाना और लागू बहुपक्षीय नियमावलियों के तहत और अधिक विश्व व्यापार को शामिल करना तथा विकसित हो रही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति के लिए गाट व्यवस्था को और अनुकूल बनाना है।

1982 में गाट के संविदाकारी पक्षों का मंत्रालयीय अधिवेशन टोक्यो दौर के परिणामों के कार्यान्वयन, और व्यापारिक प्रणाली को प्रभावित करने वाली समस्याओं की जांच करने तथा संविदाकारी पक्षों के बीच सहयोग के लिए भावी प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए जेनेवा में हुआ था। इस बैठक में, गाट नियमों और विषयों की प्रभाविता में सुधार करके कृषि को पूरी तरह बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली में लाने और निर्यात प्रतियोगिता को अधिक अनुशासन में लाने तथा साथ ही सामान्य करार के सम्भावित उपयोग सहित वस्त्र तथा परिधान के व्यापार को उदारीकृत करने के उपायों की जांच करने पर सर्वसम्मति थी। इसमें वाणिज्यिक जालसाजी के व्यापारिक पहलुओं पर गैट के ढांचे में संयुक्त कार्रवाई की उपयुक्तता का निर्धारण करने की दृष्टि से नकली वस्तुओं के मामले की जांच करने पर भी सहमति व्यक्त की गई थी। सेवाओं के संबंध में संविदाकारी पक्षों को सूचना की अदला-बदली के लिए आमंत्रित किया गया था और यह परिकल्पना की गई थी कि इसके बाद के अधिवेशन में इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या इस क्षेत्र में कोई बहुपक्षीय कार्रवाई उपयुक्त और वांछनीय है। इस बैठक के बाद में यह बात महसूस की गई थी कि इन मामलों तथा टोक्यो दौर के अन्य अनिर्णित मामलों को उठाने का एक उपयुक्त तरीका व्यापार वार्ताओं का नया दौर शुरू करना है।

उरुग्वे दौर की कार्यसूची तैयारी समिति की जनवरी से जुलाई 1986 तक हुई बैठक में हुए विचार विमर्श के आधार पर सभी भागीदारों के हितों और महत्व को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी।

उरुग्वे दौर की कार्यसूची पर गाट संविदाकारी पक्षकारों के एक विशेष मंत्रिस्तरीय अधिवेशन में सहमति हुई थी और इसे पुंटा डेल एस्टे घोषणा में मूर्त रूप दिया गया। भारत उरुग्वे दौर में 108 भागीदारों में से एक है।

उरुग्वे दौर का जो चरण 20 दिसम्बर, 1991 को संपन्न हुआ, उसमें इस गतिरोध को दूर करने के लिए बकाया मतभेदों को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास किया गया। गाट के महानिदेशक श्री आर्थर डंकल ने सरकारों के विचारार्थ एक व्यापक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें अब तक हुई वार्ताओं के परिणामों को और जिन क्षेत्रों में भागीदारों के बीच मतभेद बने हुए हैं उनके संबंध में सर्वमान्य हल शामिल किए गए हैं।

अधिकांश भागीदार सरकारों ने डंकल प्रस्तावों पर पूरी तरह संतोष व्यक्त नहीं किया। तथापि, उन्होंने इन प्रस्तावों के आधार पर वार्ता प्रक्रिया को जारी रखने के संबंध में इच्छा जाहिर की है।

इस दौर में सरकार के मुख्य उद्देश्य ये हैं: भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में अधिक बाजार प्रवेश सुनिश्चित करना; बहुपक्षीय प्रणाली के संरक्षण और उसे सुदृढ़ बनाने को ध्यान में रखते हुए गाट नियमों में सुधार लाना, और इन नियमों में विकासशील देशों की विशेष स्थिति को स्वीकार करना।

सरकार ने श्री डंकल द्वारा किए गए प्रस्तावों पर अपने दृष्टिकोण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

Indian Companies win bid for management of Sri Lankan owned tea plantations

2887. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Indian companies won bid for the management of Sri Lankan Government owned tea plantations;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the name of such companies which had participated in the bid and secured it?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Loss of market by Indian Pharmaceutical Companies in Russia

2888. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian pharmaceutical companies are losing market in Russia;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what plans Government have taken to re-capture the losing market?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) India's exports of pharmaceutical products to the erstwhile USSR had been steadily increasing in the last three years. The Indo-Russian Trade Protocol for the year 1992 provides for export of medicines to the tune of 100 million US dollars. Besides the Protocol permits transactions by way of counter-trade, barter, payments in freely convertible currency or any other internationally recognised form of business cooperation.

National Institute of Jewellery Design at Jaipur in Rajasthan

2889. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal for the setting up of a National Institute of Jewellery Design at Jaipur in Rajasthan;

(b) whether it is also a fact that a Government representative visited Jaipur for this purpose that State Government has agreed to provide a piece of land of 12 acres and all the necessary infrastructure and estimated share of one crore rupees per annum;

(c) if so, by when a decision in this regard is likely to be taken; and

(d) if no decision has so far been taken what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The Gem & Jewellery Trade is currently considering the establishment of a National Institute of Jewellery Design and Development, at a suitable location.

(b) Some years ago, the Government of Rajasthan had agreed to provide land free of cost plus all necessary infrastructural facilities and a contribution of Rs. 50 lakhs towards operational expenditure at the rate of Rs. 10 lakhs per year for five years.

(c) and (d) A decision on this is to be taken by the Trade.

Import of Shrimp Feed

2890. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the quantity and value of imports of shrimp feed during the last 3 years, year-wise;

(b) whether it is a fact that a joint sector company for the manufacture of shrimp feed has been set up in Kerala;

(c) if so, what are the details thereof